तमिलनाडु ग्रामीण विकास इंजीनियर्स एसोसिएशन

बनाम

शासन सचिव ग्रामीण विकास विभाग व अन्य

(दीवानी अपील संख्या 8758/2013)

27 सितम्बर 2013

(सुरिन्दर सिंह निज्जर और एम. वाय. इकबाल, जे.जे.)

सेवा कानून:

सीधी भर्ती और पदोन्नत सहायक इंजीनियरों के बीच वरिष्ठता- माना गया: अपीलकर्ताओं को आरडी विभाग में ओवरसियर के रूप में समाहित किया गया था। राजमार्ग विभाग में उनकी पिछली सेवा भी ओवरसियर के पद पर थी। सहायक अभियन्ता के उच्च पद पर वरिष्ठता निर्धारित किये जाने हेतू पिछली नौकरी पर सर्वेक्षक के नीचले पद के लाभ का दावा स्वीकार नही किया जा सकता। अपीलकर्ताओं को उत्तरदाता सहायक अभियंता (सीधी भर्ती) की तुलना में बहुत बाद में सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था। प्रतिवादीयाेंं ने आरडी विभाग में सहायक अभियंता के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन शुरू कर दिया था अैार इसके तहत पांच साल की सेवा पूरी कर ली थी एवं प्रासंगिक नियम के तहत सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नत होने के पात्र थे,

परिणामस्वरूप, उन्हें सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में विधिवत पदोन्नत किया गया। अतः राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को मनमाना या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन नही कहा जा सकता।

सहायक कार्यकारी अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिए कोटा-आयोजित: सहायक कार्यकारी अभियंता (आरडी) के पद पर पदोन्नति के लिए, भर्ती के एक से अधिक तरीके यानी सहायक अभियंता (आरडी) से पदोन्नति और जूनियर इंजीनियर और वरिष्ठ प्रारूप अधिकारी की फीडर श्रेणी से स्थानांतरण द्वारा भर्ती को मान्यता दी गई है और निर्धारित की गयी। इसके अलावा, सहायक अभियंता (आरडी) के पद पर भर्ती के एक से अधिक तरीके हैं यानी सीधी भर्ती और ओवरसियर की फीडर श्रेणी से स्थानांतरण द्वारा भर्ती। इसलिए,6:2:1 अनुपात प्रदान करने वाले नियम में संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा, कोटा/अनुपात का निर्धारण कार्यपालिका का विशेषाधिकार है और वर्तमान मामले में भारतीय संविधान के अन्तर्गत 309 के तहत बनाये गये अनुपाल सेवा नियम के तहत तय किया गया था।

अपीलकर्ता-एसोसिएशन (अपीलकर्ताओं) के सदस्यों को शुरू में तत्कालीन राजमार्ग और ग्रामीण कार्य विभाग में 'ओवरसियर' के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां 20 साल की सेवा करने के बाद भी, उनके

पास पदोन्नति का कोई रास्ता नहीं था। G.O. Ms. संख्या 263 ग्रामीण विभाग दिनांकित 27.12.1996 द्वारा, तमिलनाडु सरकार ने आरडी विभाग के लिए एक अलग इंजीनियरिंग विंग स्थापित करने का निर्णय लिया और सहायक अभियंता (एई), सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई), कार्यकारी अभियंता (ईई) और अधीक्षण अभियंता (एसई) के पद आरडी विभाग मे सृजित किये गये, जिन्हे अंतरिम व्यवस्था हेतू प्रतिनियुक्ति के आधार पर राज्य सरकार के अन्य तकनीकी विभागों मे कर्मियों से भरा गया था। दिनांक 25.5.1998 को, जिस तारीख को अन्य विभागों से संबंधित इंजीनियरिंग कर्मियों को लेने और भर्ती को अधिसूचित किया गया था, अपीलकर्ता राजमार्ग विभाग में ओवरसियर के पदों पर थे। दिनांक 08.03.1999 को अपीलकर्ताओं ने आरडी विभाग में ओवरसियर के रूप में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दी। दिनांक 26.09.1997 को राज्य लोक सेवा आयोग ने आरडी विभाग में सहायक अभियंताओं के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। उत्तरदाताओं-सहायक अभियंताओं को दिनांक 24.11.1998 से नवंबर, 1999 तक सीधे भर्ती किया गया था। अपीलकर्ताओं को आरडी विभाग मे अेावरसियर मे वर्ष 1997 से लाभ देते हुये दिनांक 02.09.2002 को सहायक अभियंता के रूपप मे पदोन्नत किया गया था। सहायक अभियंता-सीधी भर्ती के बीच 1:1 अनुपात पर सहायक अभियंता के पद से सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई), आरडी विभाग के पद पर पदोन्नति को प्रभावित करने के लिए अपीलकर्ताओं का प्रतिनिधित्व और

आरडी विभाग में सेवा स्थानांतरण से सहायक अभियंता-प्रमोटी से कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने G.O. Ms. संख्या 15 आरडी विभाग दिनांक 25.01.2000 की अधिसूचना-III के नियम 3(2) को अधिकारातीत होने की घोषणा एईई-सीधी भर्ती और एईई के पद पर पदोन्नत लोगों के बीच कोटा निर्धारण के अभाव को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए एक रिट जारी करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने रिट याचिका खारिज कर दी

तत्काल अपीलों में, अपीलकर्ताओं की शिकायत थी (i) कि उन्हें उनकी पिछली सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता; और (ii) एईई के पद पर पदोन्नति के लिए सीधी भर्ती और पदोन्नत व्यक्तियों के बीच 1:1 का अनुपात होना चाहिए।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए कहा कि 1.1. अपीलकर्ताओं ने राजमार्ग विभाग कि अपनी पिछली सेवा की सुरक्षा के बिना, स्वेच्छा से आरडी विभाग में शामिल होने का विकल्प चुना है, उन्हें यह शिकायत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उनके साथ सीधी भर्ती के बराबर व्यवहार नहीं किया गया है। एई के पद पर सीधी भर्ती वाले शामिल हुए। अपीलकर्ता डिग्री धारक होते हुए भी मूल विभाग राजमार्ग विभाग में ओवरसियर के पद पर कार्यरत थे। ओवरसियर के पद पर आरडी विभाग में शामिल होने का विकल्प दिए जाने के बाद, एई के रूप में अवशोषण के

लिए उनका दावा बिना किसी कानूनी या तथ्यात्मक आधार पर आधारित है।

1.2. दिनांक 25.05.1998 को, जब राज्य सरकार ने G.O.MS. संख्या 102 आरडी विभाग के माध्यम से इंजीनियरिंग स्टाफ के अवशोषण और भर्ती के आदेश जारी किए, अपीलकर्ता राजमार्ग विभाग में ओवरसियर के पदों पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन आरडी विभाग में अस्थायी सेवा पर थे। विकल्प ए के प्रयोग के आधार पर अपीलकर्ताओं को दिनांक 08.03.1999 को आरडी विभाग में समाहित कर लिया गया। इसके बाद, सरकार ने अधिसूचना G.O. Ms. संख्या 15 दिनांक 25.01.2000 द्वारा आरडी विभाग के लिए इंजीनियरिंग विंग के लिए तदर्थ नियमों के साथ अधिसूचना आईटीओ I से IV जारी की। ये अधिसूचनाएँ बी 25.5.1998 से प्रभावी हुईं, जिस तारीख को अन्य विभागों से संबंधित इंजीनियरिंग कर्मियों के अवशोषण और भर्ती को अधिसूचित किया गया था। उत्तरदाताओं की वरिष्ठता की गणना पद पर नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में की गई है। यह वरिष्ठता की गणना का एक सर्वमान्य सामान्य सिद्धांत है और इसमें कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। दरअसल, अपीलकर्ताओं की सेवा की गणना 1997 से की गई है यानी उस समय से जब उन्होंने G.O. Ms. संख्या 263 दिनांक 27.12.1996 के तहत राजमार्ग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आरडी विभाग में ओवरसियर के रूप में सेवा शुरू की थी।

1.3. अपीलकर्ताओं को दिनांक 02.09.2002 को सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था, उन्हें वर्ष 1997 से आरडी विभाग में ओवरसियर के रूप में सेवा का लाभ दिया गया था। उन्होंने सहायक अभियंता के रूप में अपनी नियुक्ति पर सवाल नहीं उठाया क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पास G.O. Ms. संख्या 295 दिनांक 14.12.2001 द्वारा संशोधित G.O. Ms. संख्या 15 दिनांक 25.1.2000 के आधार पर आरडी विभाग में ओवरसियर के रूप में पांच साल की सेवा पूरी करने पर नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं-सहायक अभियंताओं (सीधी भर्ती) ने 24-11-1998 से नवंबर, 1999 के बीच आरडी विभाग में सहायक अभियंता के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन शुरू कर दिया था। उन्हें जी नियमों के तहत सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में विधिवत पदोन्नत किया गया था। सहायक अभियंता के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी। इस प्रकार, राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को मनमाना या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता।

1.4. अपीलकर्ताओं को आरडी विभाग मे ओवरसियर के पद पर लिया गया था। राजमार्ग विभाग में उनकी पिछली सेवा भी ओवरसियर के पद पर थी। अपीलकर्ताओं ने सहायक अभियंता के उच्च पद पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए ओवरसियर के निचले पद पर पिछली सेवा का लाभ देने का दावा किया, जो केवल इस साधारण कारण से स्वीकार नहीं

किया जा सकता कि अपीलकर्ताओं ने स्वेच्छा से स्वीकार किया था और ओवरसियर के पद पर आरडी विभाग में शामिल होने का विकल्प दिया था। उस स्तर पर सहायक अभियंता के रूप में शामिल होने या पदोन्नत होने या राजमार्ग विभाग में उनके द्वारा पहले से ही प्रदान की गई सेवा का लाभ दिए जाने का कोई दावा नहीं किया गया था। इसके अलावा, उनका दावा है कि डिग्री धारक ओवरसियर को आरडी विभाग में पांच साल की सेवा प्रदान करने से छूट दी जानी चाहिए, इससे पहले कि वे सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के पात्र हो सकें, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

सब-इंस्पेक्टर रूपलाल और अन्य बनाम उपराज्यपाल मुख्य सचिव, दिल्ली और अन्य के माध्यम से 1999 (5) ई सप्ल. एससीआर 310 - प्रतिष्ठित।

2.1 इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि सहायक कार्यकारी अभियंता (आरडी) के पद पर पदोन्नति के लिए अधिसूचना संख्या G.O. Ms. संख्या 15, भर्ती के एक से अधिक तरीके यानी सहायक अभियंता (आरडी) से पदोन्नति और फीडर श्रेणी से स्थानांतरण द्वारा भर्ती कनिष्ठ अभियंता और वरिष्ठ प्रारूपण अधिकारी की नियुक्ति को मान्यता और निर्धारित किया गया है। सहायक अभियंता (आरडी) के पद पर भर्ती के एक से अधिक तरीके हैं यानी सीधी भर्ती और फीडर श्रेणी से स्थानांतरण

द्वारा भर्ती। इसलिए, नियमों में सहायक कार्यकारी अभियंता (आरडी) के पद पर नियुक्ति पर 6:2:1 (एई (आरडी) (जेई) एसडीओ से पदोन्नति) का अनुपात प्रदान किया गया है। आरडी विभाग में अपीलकर्ताओं के अवशोषण से पहले, उनके पास सहायक कार्यकारी अभियंता, कार्यकारी अभियंता या अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नत होने का कोई तरीका नहीं था। उनके समाहित होने पर ही उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नत होने का मौका मिला है। 6:2:1 के अनुपात को किसी भी तरह से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता।

2.2. अन्यथा भी, कोटा अनुपात का निर्धारण कार्यपालिका का विशेषाधिकार है। इसके अलावा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा नियमों में 6:2:1 का अनुपात तय किया गया है। यदि अपीलकर्ताओं ने यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर सामग्री नहीं रखी है कि इस तरह के अनुपात का निर्धारण स्पष्ट रूप से मनमाना है, तो सरकार की कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता है। योग्यता के आधार पर रोटा/कोटा का निर्धारण सेवा न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि 6:2:1 के अनुपात को 1:1 के अनुपात से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

केस कानुन संदर्भ

1999 (5) Suppl. SCR 310 distnguished Para 31

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं 8758/2013

उच्च न्यायालय मद्रास रिट याचिका सं 26990 की 2005 के आदेश दिनांक 29.01.2017 से।

सी. ए. 8759, 8762, 8763, 8764, 8765 की 2013

पी.एस. पटवालिया, इंदु मल्होत्रा, निशा बागची, विवेक जैन, जी निष्ठा कुमार, पूजा शर्मा, विकास मेहता अपीलकर्ता के लिए।

सुब्रमण्यम प्रसाद, एमजी, बी. बालाजी, के.वी. राठी, एम. योगेश कन्ना, ए. संथा कुमारन, एन. शोबा, श्री राम जे. थलपति, वी. अधिमूलम, एस. थानंजयन उत्तरदाताओं के लिए।

1. सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में अनुमति प्रदान की गई।

2. ये अपीलें 2005 की रिट याचिका संख्या 26990 और 26973 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 29 जनवरी, 2007 के विरुद्ध निर्देशित हैं; 2004 की 36096, 2005 की रिट अपील संख्या 500, 2004 की रिट याचिका संख्या 31416 और 2005 की 9460। इस आदेश से, उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिकाओं और रिट अपील को खारिज कर दिया।

3. चूंकि सभी अपीलों में विवाद से जुड़े तथ्य समान हैं, इसलिए हम उच्च न्यायालय द्वारा बताए गए तथ्यों का संदर्भ देंगे। यह इस न्यायालय में पक्षों द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त द्वारा पूरक होगा।

4. उच्च न्यायालय द्वारा देखे गए तथ्य यह हैं कि तमिलनाडु ग्रामीण विकास इंजीनियर्स एसोसिएशन (बाद में 'अपीलकर्ता' के रूप में संदर्भित) के सदस्यों को शुरू में तत्कालीन राजमार्ग और ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 'ओवरसियर' के रूप में नियुक्त किया गया था और विशेष रूप से तैनात किया गया था। तमिलनाडु के पंचायत संघों में सभी सिविल कार्यों/ग्रामीण कार्यों को निष्पादित करने के लिए विभिन्न पंचायत संघ। चूँकि वे पहले तत्कालीन राजमार्ग और ग्रामीण कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में थे, उनके पास विशेष रूप से सहायक अभियंता (संक्षेप में 'एई') के पद के लिए पदोन्नति के कोई उचित रास्ते नहीं थे और उनमें से कई एक ही पद पर काम कर रहे थे, यानी लगभग दो दशकों तक ओवरसियर के रूप में।

5. G.O. Ms.संख्या 263, ग्रामीण विकास विभाग (संक्षेप में 'आरडी विभाग'), दिनांक 27 दिसंबर, 1996 के आधार पर, तमिलनाडु सरकार ने आरडी विभाग के लिए एक अलग 'इंजीनियरिंग विंग' स्थापित करने का निर्णय लिया। ताकि विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं और तदनुसार सहायक अभियंता (एई) जैसे कई नए पदों पर पर्याप्त नियंत्रण

रखा जा सके। सहायक कार्यकारी अभियंता (एईई), कार्यकारी अभियंता (ईई) और अधीक्षण अभियंता (एसई) बनाए गए।

6. G.O. Ms. संख्या 102, आरडी विभाग, दिनांक 25 मई, 1998 के आधार पर, सरकार ने निर्देश दिया कि तत्कालीन राजमार्ग और ग्रामीण कार्य विभाग को आरडी विभाग में पदोन्नति और नियुक्तियों पर नियंत्रण रखना बंद कर देना चाहिए। सरकारी आदेश में एई और जूनियर इंजीनियर (जेई) के पदों पर पदोन्नति के लिए ओवरसियरों के अधिकारों को भी मान्यता दी गई है, जिनकी पूरी सेवा केवल आरडी विभाग में है। अंततः, सरकार ने आरडी विभाग में विभिन्न तकनीकी पदों के लिए सेवा नियम बनाए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत शक्तियों का उपयोग करके, 25 जनवरी, 2000 को G.O. Ms. संख्या 15 में इसे अधिसूचित किया। 14 दिसंबर, 2001 को जीओएमएस नंबर 295 (आरडी) विभाग को 25 मई, 1998 से सेवा नियमों में संशोधन करने के लिए जारी किया गया था।

7. जैसे ही आरडी विभाग में इंजीनियरिंग विंग बनाया गया, अंतरिम व्यवस्था के रूप में 'प्रतिनियुक्ति के आधार' पर तमिलनाडु सरकार के अन्य तकनीकी विभागों से कर्मियों को बुलाकर पदों को भरा गया। हालाँकि, तमिलनाडु हाईवे इंजीनियर्स एसोसिएशन ने आरडी विभाग के तहत एक अलग इंजीनियरिंग विंग के निर्माण का विरोध किया और तमिलनाडु

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (संक्षेप में 'ट्रिब्यूनल') के समक्ष 1997 के OA नंबर 253 में मूल आवेदन दायर किया। इस आवेदन को ट्रिब्यूनल ने 12 नवंबर, 1997 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। ट्रिब्यूनल के आदेश से दुखी होकर, एसोसिएशन ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष 1998 का WP नंबर 6513 दायर किया। 2 अप्रैल, 2002 के आदेश द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय ने ट्रिब्यूनल के आदेश को बरकरार रखा।

8. G.O. Ms.संख्या 15, दिनांक 25 जनवरी, 2000, और G.O. Ms. संख्या 102, दिनांक 25 मई, 1998 की संवैधानिक वैधता को व्यक्तियों के एक समूह और तमिलनाडु एसोसिएशन द्वारा ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनौती दी गई थी। 2000 के ओए नंबर 5338 और 7766 में इंजीनियरिंग स्नातक। दोनों सरकारी आदेशों को ट्रिब्यूनल ने 3 जून, 2002 के आदेश द्वारा बरकरार रखा था।

9. एई - सीधी भर्ती के एक समूह ने, आरडी विभाग में पांच साल की सेवा पूरी करने पर, ट्रिब्यूनल के समक्ष 2004 के ओए नंबर 1068 से 1081 दायर किए, प्रार्थना की कि उन्हें आरडी में एईई के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाए। तमिलनाडु सरकार के सामान्य नियमों के नियम 39 के तहत विभाग। ट्रिब्यूनल ने 16 मार्च, 2004 के आदेश द्वारा सरकार और निदेशक, आरडी विभाग को सामान्य नियमों के नियम 39 के तहत आवेदकों पर विचार करने और पदोन्नति देने का निर्देश दिया। यह

भी माना गया कि पैनल बनाकर नियमित पदोन्नति एवं चयन किया जा सकता है। इस आदेश को अपीलकर्ताओं ने 2004 की रिट याचिका संख्या 34029 और 34040 और 2005 की 1174 में चुनौती दी थी।

10. अपीलकर्ता-एसोसिएशन ने एईई के पद पर पदोन्नति के लिए एई-सीधी भर्ती और एई-प्रमोटी के बीच 1:1 का अनुपात तय करने के लिए प्रतिवादी को अभ्यावेदन दिया। उपरोक्त अनुपात को एई की श्रेणी में एई- के बीच कैडर की ताकत के आधार पर तय करने का अनुरोध किया गया था।

सीधी भर्ती और एई- प्रमोटी, जो 1:1 है। एईई के प्रमोशनल पद के लिए भी यही अनुपात बनाए रखने की मांग की गई थी।

11. यह कहा गया है कि G.O. Ms. संख्या 15 में परिकल्पित अनुपात के संदर्भ के बिना, प्रतिवादी संख्या 2 ने सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों के लिए एक सामान्य वरिष्ठता सूची बनाने की मांग की। अपीलकर्ता-एसोसिएशन ने 2004 के WPNo.26276 में सामान्य वरिष्ठता सूची को चुनौती दी। 2 सितंबर, 2004 को उक्त WP में अंतरिम रोक लगा दी गई। बाद में, अपीलकर्ता-एसोसिएशन ने नई रिट दायर करने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिका वापस ले ली।

12. इसके तुरंत बाद प्रतिवादी नंबर 1 ने 29 अक्टूबर, 2004 को जीओ (2 डी) नंबर 116 जारी करके सीधी भर्ती के एक समूह की पदोन्नति

की, जिन्होंने एईई के रूप में 5 साल की सेवा पूरी कर ली थी। इसके बाद जीओ (डी) नंबर जारी किया गया। 966 (आरडी) (ई1) दिनांक 16 नवंबर, 2004 द्वारा इन पदोन्नतियों के पदस्थापन आदेश जारी किए गए। अपीलकर्ता- एसोसिएशन ने तब 2004 का डब्लूपी नंबर 36096 दायर किया, जिसमें एईई के रूप में सीधी भर्ती की पदोन्नति और पोस्टिंग को चुनौती दी गई थी।

13. अपीलकर्ता-एसोसिएशन ने 2004 का W.P. नंबर 31416 भी दायर किया, जिसमें प्रतिवादियों को 'सहायक अभियंता' के पद पर 1:1 के अनुपात पर सहायक अभियंता के पद से सहायक कार्यकारी अभियंता, आरडी विभाग के पद पर पदोन्नति करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की रिट मांगी गई।

14. इस बीच, उच्च न्यायालय ने 2004 की रिट याचिका 35315 में 2 दिसंबर, 2004 को एक आदेश पारित किया, जिसमें सरकार को 2004 के ओए नंबर 1799 में ट्रिब्यूनल के आदेश को लागू करने और प्रमोटी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। यदि कोई अन्य बाधा न हो, तो इसे राजमार्ग विभाग से समाहित कर लिया गया। अपीलकर्ता-एसोसिएशन ने एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध 2005 की रिट अपील संख्या 500 दायर की।

15. सरकार ने पत्र दिनांक 29 दिसंबर, 2004 द्वारा अपीलकर्ता-एसोसिएशन के 1:1 का अनुपात तय करने के अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया कि दोनों श्रेणियों की पदोन्नति ज्वाइनिंग की तारीख के आधार पर की जानी है। स्रोत की परवाह किए बिना सहायक अभियंता के रूप में। इसके चलते अपीलकर्ता-एसोसिएशन ने 29 दिसंबर, 2004 को सरकार द्वारा जारी अस्वीकृति पत्र को रद्द करने के लिए प्रार्थना करते हुए 2005 की WP संख्या 9460 दायर की।

16. अपीलकर्ता-एसोसिएशन ने 2005 की डब्लूपी संख्या 26973 भी दायर की, जिसमें उत्तरदाताओं को 25 मई, 1998 से सहायक अभियंताओं के रूप में दी गई पदोन्नति को पूर्वव्यापी प्रभाव देने का निर्देश देने वाले परमादेश की रिट जारी करने की मांग की गई, यानी, जिस तारीख से सेवा शुरू हुई थी। 14 दिसंबर, 2001 को जीओएमएस संख्या 295 ग्रामीण विकास (ई1) विभाग में अधिसूचित 'एई-प्रमोटी' के नियम प्रभावी हुए।

17. 'एई' के लिए अनुपात तय न होने से व्यथित -प्रमोटियों के विभिन्न अभ्यावेदन के बावजूद, अपीलकर्ता-एसोसिएशन के सदस्यों ने 2005 की एक रिट याचिका संख्या 26990 दायर की, जिसमें G.O. Ms. संख्या 15, आरडी विभाग, दिनांक की अधिसूचना-III के नियम 3 (2) की घोषणा करते हुए रिट जारी करने की मांग की गई। 25 जनवरी, 2000 को

एई-सीधी भर्ती और एईई के पद पर पदोन्नत लोगों के बीच कोटा निर्धारण के अभाव को अधिकारातीत माना गया।

18. आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने माना है कि अवशोषण से पहले और अवशोषण के तुरंत बाद आरडी विभाग में अपीलकर्ताओं की सेवा निचले पद, यानी ओवरसियर में थी। इसलिए, उन्हें आरडी विभाग में सहायक अभियंता के रूप में शामिल होने वाले सीधी भर्ती के साथ बराबर नहीं किया जा सकता है। ओवरसियर का पद सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए फीडर पद था। आगे यह देखा गया कि बेशक, अपीलकर्ताओं ने स्वेच्छा से ओवरसियर के रूप में शामिल होने का विकल्प दिया था। इसलिए, वे सहायक अभियंताओं के बराबर होने का दावा नहीं कर सकते। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं को, अवशोषण के बाद, पदोन्नति के लिए विचार करके उदार व्यवहार दिया गया और वास्तव में, उन्हें एई के रूप में पदोन्नत किया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह सरकार के इस विशिष्ट रुख को हल्के में नजरअंदाज नहीं कर सकता कि एईई के पद पर पदोन्नति के लिए एई के पद पर 5 साल की न्यूनतम योग्यता सेवा इस कारण से निर्धारित की गई है कि पदधारियों को आवश्यक व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करना चाहिए। 'उच्च ज़िम्मेदारियाँ' लेने से पहले ताकि इंजीनियरिंग सेवाओं में प्रशासनिक दक्षता हासिल की जा सके। अपीलकर्ता यह दावा नहीं कर सकते कि राजमार्ग विभाग में 20 वर्षों तक ओवरसियर के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को आरडी

विभाग में पदोन्नति के लिए ध्यान में रखा जाएगा। वे उस मुद्रा का उपयोग नहीं कर सकते जो विलुप्त हो चुकी है और प्रचलन में नहीं है। पहले से ही, उन्हें अच्छी तरह से पुरस्कृत किया गया था क्योंकि उनकी पिछली सेवाओं को उनके अवशोषण से बहुत पहले, यानी 1997 से, ध्यान में रखा गया था; जबकि, सीधे भर्ती किए गए लोगों की सेवाओं की गणना उनके सरकारी सेवा में प्रवेश करने की तारीख से की जाती थी; इसलिए, वास्तव में लाभ केवल अपीलकर्ताओं को ही दिया गया है, सीधी भर्ती वाले लोगों को नहीं। इक्विटी में भी, अपीलकर्ताओं का दावा बिना किसी योग्यता के था क्योंकि आरडी विभाग में शामिल होने के बाद, उन्हें पदोन्नति दी गई है और सीधी भर्ती के बराबर खड़ा कर दिया गया है। इसलिए, एकीकृत कैडर में आगे वर्गीकरण और पदोन्नति के उद्देश्य से पांच साल के अनुभव की छूट मांगने का कोई औचित्य नहीं है। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि एक बार सीधी भर्ती और पदोन्नत लोगों को एक कैडर में समाहित कर लिया जाएगा। वे एक वर्ग बनाते हैं और उन्हें पदोन्नति के उद्देश्य से आगे वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यह अपीलकर्ताओं का मामला नहीं है कि नियमों में प्रदान किया गया अपेक्षित अनुभव केवल उनके मामले के संबंध में लागू किया जाता है और सीधी भर्ती को शिखर तक पहुंचने के लिए सीढ़ी चढ़ने की छूट दी जाती है। वास्तव में, हालांकि अपीलकर्ताओं का कहना है कि उन्हें पूर्वव्यापी पदोन्नति दी जानी चाहिए थी, माना जाता है कि वे आज तक पदोन्नति के लिए योग्य नहीं हैं, ऐसे में, ओवरसियर के

रूप में उनकी सहमति से आरडी विभाग में उनका अवशोषण 8 मार्च, 1999 को हुआ था; एई के रूप में उनकी पदोन्नति 2 सितंबर, 2002 को हुई थी; और वे एई के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर लेंगे। केवल 2 सितंबर, 2007 को। आज की तारीख में, वे सभी सीधी भर्ती से कनिष्ठ हैं, इसलिए, वे प्रक्रिया और वैधानिक प्रावधानों के विपरीत अनुचित तरीके से राहत नहीं मांग सकते हैं ताकि उनके वरिष्ठों/सीधी भर्ती से प्राप्त अधिकार को नष्ट किया जा सके। यह दोहराया जाता है कि प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम बनाए गए हैं संविधान का अनुच्छेद 309 , वैधानिक होने के कारण, सनकी और तुच्छ कारणों से महाभियोग नहीं लगाया जा सकता है। सेवा कानून में, यह स्थापित सिद्धांत है कि विभिन्न फीडर श्रेणियों के बीच कोटा का निर्धारण नियोक्ता/प्राधिकरण का विशेषाधिकार है। इस दावे को कायम रखने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष कोई वैध आधार नहीं उठाया गया या अजेय तर्क नहीं दिया गया कि ट्रिब्यूनल के आदेश हस्तक्षेप की आवश्यकता वाली कमजोरियों से ग्रस्त हैं। इन कारणों से, उच्च न्यायालय ने माना है कि सरकारी आदेश का विवादित हिस्सा किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करता है और प्रार्थना के अनुसार कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएँ और रिट अपील खारिज कर दी गईं।

19. हमने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

20. अपीलकर्ताओं द्वारा की गई दलीलें इस प्रकार हैं: यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार ने 1997 में सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करके 1996 में सृजित सहायक अभियंता के पद को भरने में मनमाने ढंग से कदम उठाया है, जबकि अपीलकर्ता (ओवरसियर) अधिक योग्य और अनुभवी होने के साथ-साथ स्थानांतरण द्वारा भर्ती के लिए उपलब्ध थे। G.O. Ms. संख्या 15 दिनांक 25 जनवरी, 2000 के संदर्भ में। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सीधी भर्ती वाले सहायक इंजीनियरों के संबंध में भर्ती नियमों को 26 सितंबर, 1997 से पूर्वव्यापी रूप से अधिसूचित किया गया था, जिससे सीधी भर्ती वाले सहायक इंजीनियरों की सामूहिक पदोन्नति की सुविधा मिल सके। सहायक कार्यकारी अभियंता को. अपीलकर्ताओं ने आगे दावा किया कि G.O. Ms. संख्या 15 दिनांक 25 जनवरी, 2000 के प्रावधानों की गलत व्याख्या की गई है ताकि यह शर्त लगाई जा सके कि सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले ओवरसियर को भी सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नत होने के लिए 5 साल की सेवा की आवश्यकता होगी। . ऐसी शर्त लगाने से अपीलकर्ता-एसोसिएशन के सदस्यों और पिछले दो दशकों में ओवरसियर के रूप में उनकी पिछली सेवा से वंचित हो गए हैं। अपीलकर्ताओं ने यह भी दावा किया कि G.O. Ms. संख्या 295 दिनांक 14 दिसंबर, 2001 उन पर लागू नहीं होगी, इसके परिणामस्वरूप वे पूर्वव्यापी रूप से अपने सर्वोत्तम अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि वे 25 मई, 1998 से सहायक

इंजीनियरों के रूप में स्थानांतरित होने के हकदार हैं, जिस तारीख को सहायक इंजीनियरों के लिए सेवा नियम अधिसूचित किए गए थे। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सहायक अभियंता के पद पर भर्ती के लिए सीधी भर्ती और अपीलकर्ताओं के बीच प्रदान किया गया 1: 1 का अनुपात सहायक कार्यकारी इंजीनियरों के अगले पदोन्नति पद के लिए भी बनाए रखा जाना चाहिए।

21. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं ने कहा कि अपीलकर्ताओं के पास 1997 में शुरू की गई सीधी भर्ती को चुनौती देने का कोई कानूनी कारण नहीं है। वे 25 तारीख के जीओ एमएस नंबर 102 के जारी होने तक आरडी विभाग में अवशोषण के लिए भी पात्र नहीं थे। मई, 1998. उत्तरदाताओं के अनुसार, विभिन्न पद अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति और स्थानांतरण पर दिनांक 27 दिसंबर, 1996 के G.O. Ms. संख्या 263 के तहत भरे गए थे। लेकिन यह एक अस्थायी व्यवस्था थी जो 3 साल की अवधि के लिए की गई थी. 25 मई, 1998 को G.O. Ms. संख्या 102 जारी होने तक आरडी विभाग में अन्य विभागों से लिए गए इंजीनियरिंग कर्मियों के अवशोषण और भर्ती के लिए कोई योजना नहीं थी। पद को सीधे भरने में कोई बाधा नहीं थी। G.O. Ms. संख्या 263 दिनांक 27 दिसंबर, 1996 के तहत सृजित पद की भर्ती। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता गलत दावा कर रहे हैं कि सीधी भर्ती वाले लोगों को 26 सितंबर, 1997 से पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई अनुचित लाभ दिया गया है। उपरोक्त तिथि केवल

सहायक अभियंता सीधी भर्ती की भर्ती को नियमित करने के लिए दिया गया था। अन्य सभी उद्देश्यों के लिए, सहायक अभियंता सीधी भर्ती द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को 1998 से ध्यान में रखा गया है। उत्तरदाताओं ने दावा किया कि वास्तव में अपीलकर्ताओं को उनके अवशोषण से बहुत पहले की तारीख से सेवा का लाभ दिया गया है, उनकी सेवाएं 1997 से ध्यान में रखा गया जबकि उन्हें 1998 में आरडी विभाग में समाहित नहीं किया गया था। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तब प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष यह मुद्दा नहीं उठाया कि G.O. Ms. संख्या 15 दिनांक 25 जनवरी, 2000 को क्या करना चाहिए सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नत होने के लिए सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री धारकों के लिए ओवरसियर के रूप में 5 साल की सेवा की शर्त लगाने की व्याख्या नहीं की जाएगी। उच्च न्यायालय के समक्ष एकमात्र निवेदन यह था कि सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर नियुक्ति भी 1:1 के अनुपात में की जानी चाहिए न कि 6:2:1 के अनुपात में जैसा कि G.O. Ms. संख्या की अधिसूचना में उल्लिखित है। 15 दिनांक 25 जनवरी, 2000। उत्तरदाताओं द्वारा यह भी बताया गया है कि अन्यथा भी G.O. Ms. संख्या 15 को G.O. Ms. संख्या द्वारा संशोधित किया गया था। 295 दिनांक 14 दिसंबर, 2001 ने स्थानांतरण द्वारा भर्ती के लिए योग्यता में संशोधन किया और प्रावधान किया कि उम्मीदवार के पास "सिविल इंजीनियरिंग में बीई की डिग्री होनी चाहिए" या "एआईएमई उत्तीर्ण होना चाहिए" और (ii) "कम से

कम समय तक ओवरसियर के रूप में सेवा प्रदान की होनी चाहिए" 5 वर्ष से अधिक।" G.O. Ms. संख्या 295 को अपीलकर्ताओं द्वारा कभी चुनौती नहीं दी गई।

22. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा कि अपीलकर्ता 20 वर्षों तक ओवरसियर के रूप में पिछली सेवा के आधार पर किसी भी लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। वे अच्छी तरह से जानते थे कि राजमार्ग विभाग में उनकी सेवाओं को आरडी विभाग में वरिष्ठता के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा, जब उन्होंने 8 मार्च, 1999 को ही आरडी विभाग में ओवरसियर के रूप में शामिल होने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। विकल्प देने के बाद, वे अब यह शिकायत नहीं कर सकते कि उन्होंने 20 साल की सेवा का लाभ खो दिया है। अपीलकर्ताओं की प्रस्तुति के संबंध में कि G.O. Ms. संख्या 295 दिनांक 14 दिसंबर, 2001 अपीलकर्ताओं के निहित अधिकारों को प्रभावित नहीं कर सकती है। उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता का यह अनुरोध 2005 के WP संख्या 26973 में उनके द्वारा की गई प्रार्थना के विपरीत है, जिसमें अपीलकर्ताओं ने उपरोक्त अधिसूचना पर भरोसा किया था। उपरोक्त रिट याचिका में, अपीलकर्ताओं ने विशेष रूप से G.O. Ms. संख्या के आधार पर पूर्वव्यापी पदोन्नति दिए जाने की प्रार्थना की थी।

295. उत्तरदाताओं ने दावा किया कि अपीलकर्ताओं की यह दलील कि वे 25 मई, 1998 से सहायक अभियंता के रूप में स्थानांतरित होने के हकदार हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि उस तारीख को वे ओवरसियर के निचले पद पर काम कर रहे थे और इसके अलावा वे इसके सदस्य भी थे। राजमार्ग विभाग. यह केवल उनके विकल्प के आधार पर था कि उन्हें 1998 में आरडी विभाग में ओवरसियर के रूप में शामिल किया गया था। दूसरी ओर, सहायक अभियंता सीधी भर्ती 1998 में ही सेवा में आ गए थे। उत्तरदाताओं ने आगे कहा कि कार्यकारी अभियंता के पदोन्नति पद के लिए 1:1 का अनुपात बनाए रखने के संबंध में अपीलकर्ताओं के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसे अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष छोड़ दिया था।

23. हमने पक्षों के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है।

24. संक्षेप में, अपीलकर्ता की शिकायत दो प्रकार की है:-

(i) उन्हें उनकी पिछली सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता।

(ii) एईई के पद पर पदोन्नति के लिए सीधी भर्ती/प्रमोटी के बीच 1:1 का अनुपात होना चाहिए।

25. हमारी राय में, अपीलकर्ता अब यह दावा नहीं कर सकते कि राजमार्ग विभाग में पिछली सेवा को आरडी विभाग में मान्यता दी जानी

चाहिए। पहले यह देखा गया है कि अपीलकर्ता-एसोसिएशन के सदस्यों को शुरू में तत्कालीन राजमार्ग और ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ओवरसियर के रूप में नियुक्त किया गया था और तमिलनाडु के पंचायत संघों में सभी सिविल कार्यों/ग्रामीण कार्यों को निष्पादित करने के लिए विशेष रूप से विभिन्न पंचायत संघों में तैनात किया गया था। चूँकि वे पहले तत्कालीन राजमार्ग और ग्रामीण कार्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में थे, उनके पास विशेष रूप से एई के पद के लिए पदोन्नति के कोई उचित रास्ते नहीं थे, उनमें से कई लगभग दो दशकों से एक ही पद यानी ओवरसियर के रूप में काम कर रहे थे। 27 दिसंबर, 1996 को सरकार ने आरडी विभाग के लिए एक अलग इंजीनियरिंग विंग (जीओएम नंबर 263; आरडी विभाग दिनांक 27 दिसंबर, 1996) की स्थापना की। विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं पर पर्याप्त नियंत्रण रखने के लिए यह आवश्यक था। तीन वर्ष की अवधि के लिए सहायक अभियंताओं के 384 पद सृजित किये गये। ये पद राजमार्ग और ग्रामीण कार्य, लोक निर्माण विभाग, कृषि इंजीनियरिंग, तमिलनाडु जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड इत्यादि जैसे अन्य विभागों से इंजीनियरिंग कर्मियों को आकर्षित करके सेवा के आधार पर प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण पर पूरी तरह से अस्थायी आधार पर भरे गए थे। अपीलकर्ता हालांकि संबंधित थे राजमार्ग विभाग पहले से ही कई वर्षों से ग्रामीण विकास विभाग में ओवरसियर के कार्यों का निर्वहन कर रहा था। 26 सितंबर, 1997 को तमिलनाडु लोक सेवा आयोग ने आरडी विभाग में

सहायक अभियंताओं के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया। उत्तरदाताओं-सहायक अभियंताओं की सीधी भर्ती 24 नवंबर, 1998 से नवंबर, 1999 तक की गई थी। विभिन्न विभागों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर तकनीकी कर्मचारियों को बुलाने से राज्य के साथ-साथ केंद्र की विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू करने में प्रशासनिक कठिनाइयाँ पैदा हो रही थीं। यह देखा गया कि कार्यान्वयन प्राधिकरण के पास अन्य विभागों के इंजीनियरिंग कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त शक्तियां नहीं थीं। इसलिए, विशुद्ध रूप से प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह अनिवार्य आवश्यकता बन गई थी कि आरडी विभाग का अपना एक इंजीनियरिंग विंग होना चाहिए। आगे यह देखा गया कि पहले कदम के रूप में 27 दिसंबर, 1996 को G.O. Ms. संख्या 263 आरडी विभाग जारी किया गया था। सरकार ने यूनियन इंजीनियरों के एक यानी 384 अतिरिक्त पद सृजित किये थे सहायक कार्यकारी अभियंताओं के अतिरिक्त पद और कार्यकारी अभियंताओं के 28 पद। इन पदों के लिए आवश्यक इंजीनियरों को राजमार्ग और ग्रामीण कार्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि इंजीनियरिंग, तमिलनाडु जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड और अन्य तकनीकी विभागों से लिया गया था। 25 मई 1998 को, राज्य ने G.O. Ms. संख्या 102 आरडी विभाग के माध्यम से इंजीनियरिंग स्टाफ के अवशोषण और भर्ती के लिए आदेश जारी किए, जो निम्नानुसार प्रदान किए गए: "III। हालाँकि ओवरसियर के पद केवल पंचायत यूनियनों में पाए जाते हैं, लेकिन पदधारियों को ब्लॉक

इंजीनियरों/सहायक इंजीनियरों (आरडी) के कुछ पदों पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता है क्योंकि वे वर्तमान में राजमार्ग विभागों के कर्मचारी हैं। उन्हें व्यक्तिगत विकल्प प्राप्त करके आरडी विभाग में स्थायी रूप से समाहित करने की आवश्यकता है और उसके बाद ही उनकी पदोन्नति का प्रश्न उठाया जा सकता है। ... मुख्य अभियंता (एच एंड आरडब्ल्यू) से उन सभी कर्मियों से विकल्प प्राप्त करने और उन्हें ग्रामीण विकास विभाग के निपटान में रखने का अनुरोध किया जा सकता है। चतुर्थ. ओवरसियर और जूनियर ड्राफ्ट्समैन की फीडर श्रेणियों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए ब्लॉक इंजीनियरों/सहायक अभियंता (आरडी) की श्रेणी में 209 पद निर्धारित किए जाएंगे। लेकिन यह मार्ग उनके लिए तभी खुला होगा जब वे अपने विकल्प का प्रयोग करेंगे और स्थायी रूप से आरडी विभाग में शामिल हो जायेंगे....."

26. यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि 25 मई, 1998 को, अपीलकर्ता राजमार्ग विभाग में ओवरसियर के पदों पर कार्यरत थे, लेकिन G.O. Ms. संख्या 263 दिनांक 27 दिसंबर, 1996 के तहत आरडी विभाग में अस्थायी सेवा पर थे। अपीलकर्ताओं को आरडी विभाग में स्थायी रूप से शामिल होने का अवसर दिया गया, उनसे यह विकल्प मांगा गया कि क्या वे शामिल होने के इच्छुक हैं। विकल्प के उपरोक्त अभ्यास के आधार पर, अपीलकर्ताओं को 8 मार्च 1999 को आरडी विभाग में समाहित कर लिया गया। इसके बाद, सरकार ने अधिसूचना G.O. Ms. संख्या 15 दिनांक 25

द्वारा आरडी विभाग के लिए इंजीनियरिंग विंग के लिए तदर्थ नियम जारी किए। जनवरी, 2000. G.O. Ms. संख्या 15 में चार अधिसूचनाएं (I से IV) क्रमशः अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक कार्यकारी अभियंता और सहायक अभियंता के पद पर भर्ती की योग्यता और तरीका प्रदान करती हैं। अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता और सहायक कार्यकारी अभियंता की पहली तीन श्रेणियों में किसी भी सीधी भर्ती की अनुमति नहीं थी। इसलिए, ये अधिसूचनाएं 25 मई, 1998 से प्रभावी हुईं, जिस तारीख को अन्य विभागों से संबंधित इंजीनियरिंग कर्मियों के अवशोषण और भर्ती को अधिसूचित किया गया था। यह केवल सहायक अभियंताओं के संबंध में अधिसूचना IV के तहत था जो सीधी भर्ती का प्रावधान करता था। चूंकि आरडी विभाग में सहायक अभियंता के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया टीएनपीएससी द्वारा 26 सितंबर, 1997 की अधिसूचना के माध्यम से शुरू की गई थी, सहायक अभियंता के संबंध में अधिसूचना IV के तहत नियमों को 26 सितंबर को लागू माना गया था। , 1997. कार्यकारी आदेश के आधार पर टीएनपीएससी के माध्यम से सीधे आरडी विभाग के लिए सहायक अभियंता की भर्ती के लिए की गई कार्रवाई को नियमित करना आवश्यक था। हालाँकि, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नियमों के इस तरह के पूर्वव्यापी कार्यान्वयन से वरिष्ठता के मामले में सीधी भर्ती वाले लोगों को कोई लाभ नहीं मिलता है। उत्तरदाताओं की वरिष्ठता की गणना पद पर नियुक्ति की तारीख के संदर्भ में की गई है। यह

वरिष्ठता की गणना का एक सर्वमान्य सामान्य सिद्धांत है और इसमें कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। दरअसल, अपीलकर्ताओं की सेवा की गणना 1997 से की गई है यानी उस समय से जब उन्होंने G.O. Ms. संख्या 263 दिनांक 27.12.1996 के तहत राजमार्ग विभाग से प्रतिनियुक्ति पर आरडी विभाग में ओवरसियर के रूप में काम करना शुरू किया था।

27. अपीलकर्ताओं ने स्वेच्छा से अपनी पिछली सेवा की सुरक्षा के बिना आरडी विभाग में शामिल होने का विकल्प चुना है, उन्हें अब यह शिकायत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उनके साथ सीधी भर्ती के बराबर व्यवहार नहीं किया गया है। हमने ऊपर देखा कि AE के पद पर सीधी भर्ती वाले लोग शामिल हुए। अपीलकर्ताओं को, भले ही उनमें से कुछ के पास डिग्री योग्यता थी, ओवरसियर के पद पर शामिल कर लिया गया। वे डिग्री धारक होते हुए भी मूल विभाग राजमार्ग विभाग में ओवरसियर के पद पर कार्यरत थे। जैसा कि पहले देखा गया था, वे कैरियर में उन्नति की किसी भी संभावना के बिना राजमार्ग विभाग में रुके हुए थे। इसलिए, उन्होंने स्वेच्छा से आरडी विभाग में ओवरसियर के रूप में शामिल होने का विकल्प दिया, भले ही उनके पास डिग्री योग्यता थी। ओवरसियर के पद पर आरडी विभाग में शामिल होने का विकल्प दिए जाने के बाद, एई के रूप में शामिल होने का उनका दावा बिना किसी कानूनी या तथ्यात्मक औचित्य के है।

28. यहां यह भी ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि अपीलकर्ताओं को 2 सितंबर, 2002 को सहायक अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था, उन्हें वर्ष 1997 से आरडी विभाग में ओवरसियर के रूप में सेवा का लाभ दिया गया था। अपीलकर्ताओं ने उनकी नियुक्ति पर सवाल नहीं उठाया था चूंकि सहायक अभियंता अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें G.O. Ms. संख्या 15 दिनांक 25 जनवरी, 2000 के आधार पर आरडी विभाग में ओवरसियर के रूप में पांच साल की सेवा पूरी करने पर नियुक्त किया गया था, जैसा कि G.O. Ms. संख्या 295 दिनांक 14 द्वारा संशोधित किया गया था। दिसंबर, 2001. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं- सहायक अभियंताओं (सीधी भर्ती) ने 24 नवंबर, 1998 से नवंबर, 1999 तक आरडी विभाग में सहायक अभियंता के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन शुरू कर दिया था। इसलिए, उन्होंने सहायक अभियंता के रूप में पांच साल की सेवा पूरी कर ली थी। प्रासंगिक नियमों के तहत नवंबर, 2003 से नवंबर, 2004 के बीच की अवधि के लिए (G.O. Ms. संख्या 15 दिनांक 25 जनवरी, 2000 में अधिसूचना III) नियमों के तहत सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नत होने के पात्र हैं। नतीजतन, उन्हें सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में विधिवत पदोन्नत किया गया। हमारी राय में, राज्य द्वारा की गई कार्रवाई को मनमाना या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

29. अपीलकर्ताओं का यह दावा कि सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति 1:1 के अनुपात में की जानी चाहिए, भी पूरी तरह से किसी भी योग्यता से रहित है। अपीलकर्ताओं ने इस तरह के अनुपात का दावा इस आधार पर किया कि सीधी भर्ती वाले-प्रतिवादी उम्र में बहुत छोटे हैं। आरडी विभाग में शामिल होने से पहले अपीलकर्ता राजमार्ग विभाग में 20 साल से अधिक समय बिता चुके थे। इसलिए, यदि पदोन्नति पूरी तरह से वरिष्ठता के आधार पर होनी है, तो अपीलकर्ताओं को उच्च रैंक पर पदोन्नति के लिए कभी बदलाव नहीं मिलेगा। उन्हें केवल सहायक अभियंता के रूप में सेवानिवृत्त होना होगा क्योंकि एईई और उससे ऊपर के पद पर उनकी पदोन्नति के रास्ते एई-सीधी भर्ती द्वारा पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे, जो पदोन्नत सहायक अभियंता से कम से कम 8 वर्ष छोटे हैं। अपीलकर्ताओं का यह भी मामला है कि सहायक अभियंता के पद पर नियुक्ति के लिए निर्धारित 1:1 का अनुपात सहायक कार्यकारी अभियंता के अगले पदोन्नति पद के लिए बनाए रखा जाना चाहिए। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि सहायक कार्यकारी अभियंता (आरडी) अधिसूचना संख्या III G.O. Ms. संख्या 15 के पद पर पदोन्नति के लिए, भर्ती के एक से अधिक तरीके यानी सहायक अभियंता (आरडी) से पदोन्नति और फीडर श्रेणी से स्थानांतरण द्वारा भर्ती कनिष्ठ अभियंता और वरिष्ठ प्रारूपण अधिकारी की नियुक्ति को मान्यता और निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, यह भी रिकॉर्ड की बात है कि सहायक अभियंता (आरडी)

के पद पर भर्ती के एक से अधिक तरीके हैं यानी सीधी भर्ती और केवल ओवरसियर की फीडर श्रेणी से स्थानांतरण द्वारा भर्ती। इसलिए, नियमों में सहायक कार्यकारी अभियंता (आरडी) के पद पर नियुक्ति पर 6:2:1 (एई (आरडी); जेई; एसडीओ से पदोन्नति) का अनुपात प्रदान किया गया है। हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि यह अनुपात 1:1 होना चाहिए, अन्यथा वे जूनियर इंजीनियर के पद पर बने रहेंगे। हम अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा दी गई दलीलों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। आरडी विभाग में अपीलकर्ताओं के अवशोषण से पहले, उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नत होने का कोई मौका नहीं था, कार्यकारी अभियंता या अधीक्षण अभियंता। यह उनके अवशोषण पर ही है कि अब उन्हें उच्च पदों पर पदोन्नत होने का मौका मिलता है। हम अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील की दलीलों से सहमत होने में असमर्थ हैं कि उपरोक्त अनुपात किसी भी तरह से उल्लंघनकारी है।

30. अन्यथा भी, कोटा/अनुपात का निर्धारण कार्यपालिका का विशेषाधिकार है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राज्यपाल की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा नियमों में 6:2:1 का अनुपात तय किया गया है। अपीलकर्ताओं द्वारा यह स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड सामग्री प्रस्तुत करने की अनुपस्थिति में कि इस तरह के अनुपात का निर्धारण स्पष्ट रूप से मनमाना है, सरकार की कार्रवाई को रद्द नहीं किया जा सकता है। योग्यता

के आधार पर रोटा/कोटा का निर्धारण सेवा न्यायशास्त्र में अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है। इसलिए, हम अपीलकर्ताओं की दलीलों में कोई योग्यता नहीं देखते हैं कि 6:2:1 के अनुपात को 1:1 के अनुपात से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

31. इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि डिग्री योग्यता रखने वाले ओवरसियर को सहायक कार्यकारी अभियंता के आधार पर आगे की पदोन्नति पर विचार करने के लिए आरडी विभाग में पांच साल की सेवा प्रदान करने से छूट दी जानी चाहिए। हम इस निवेदन को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि अपीलकर्ताओं ने स्वेच्छा से ओवरसियर के रूप में शामिल होने का विकल्प दिया था। यदि अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसका मतलब यह होगा कि अपीलकर्ता वास्तव में सहायक अभियंता के पद पर समाहित हो गए थे जो तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। नियमों के तहत, एक सहायक अभियंता को आरडी विभाग में पांच साल की सेवा पूरी करने पर ही सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है। इसलिए, अपीलकर्ताओं की इस दलील को स्वीकार करना संभव नहीं होगा कि राजमार्ग विभाग में अपीलकर्ताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को आरडी विभाग में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के स्थान पर लिया जाना चाहिए। वास्तव में, अपीलकर्ताओं को राजमार्ग विभाग में दो साल की सेवा का लाभ पहले ही इस आधार पर दिया जा चुका है कि वे वास्तव में 1997 से

आरडी विभाग में काम कर रहे थे। लेकिन ऐसी रियायत अपीलकर्ताओं के पक्ष में दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं बनाएगी। कि राजमार्ग विभाग में प्रदान की गई सेवाओं को आरडी विभाग में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाना चाहिए। इसलिए, हम इस दलील में कोई योग्यता नहीं देखते हैं कि डिग्री धारक ओवरसियर को आरडी विभाग में पांच साल की सेवा प्रदान करने से छूट दी जानी चाहिए, इससे पहले कि वे सहायक कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नति के लिए पात्र हो सकें। अपीलकर्ताओं ने सब-इंस्पेक्टर रूपलाल और अन्य बनाम के फैसले पर भरोसा किया था। मुख्य सचिव, दिल्ली और अन्य के माध्यम से उपराज्यपाल[1] ने इस दलील का समर्थन किया कि उनकी 20 साल की पिछली सेवा को ख़त्म नहीं किया जा सकता। उपरोक्त निवेदन को केवल इस कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं को आरडी विभाग में ओवरसियर के रूप में शामिल किया गया था। राजमार्ग विभाग में उनकी पिछली सेवा भी ओवरसियर के पद पर थी। रूपलाल के मामले में (सुप्रा), अपीलकर्ता बोर्डर सुरक्षा बल के उप-निरीक्षक थे, जिन्हें शुरू में उप-निरीक्षक (कार्यकारी) के रूप में दिल्ली पुलिस में प्रतिनियुक्ति पर लिया गया था और बाद में उसी क्षमता में दिल्ली पुलिस में शामिल कर लिया गया था। दिल्ली पुलिस में उनकी वरिष्ठता तय करते समय उनके द्वारा बीएसएफ में उप-निरीक्षक के रूप में की गई सेवा को ध्यान में नहीं रखा गया। इसलिए, इस न्यायालय ने माना कि ऐसा कोई कारण नहीं

है कि स्थानांतरित पद पर समकक्ष कैडर में समाहित होने पर अपीलकर्ताओं को मूल विभाग में उनकी सेवा की गणना करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें अपीलकर्ताओं ने सहायक अभियंता के उच्च पद पर वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए ओवरसियर के निचले पद पर पिछली सेवा के लाभ का दावा किया। उपरोक्त प्रस्तुतीकरण को इस साधारण कारण से स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया था और ओवरसियर के पद पर आरडी विभाग में शामिल होने का विकल्प दिया था। उस स्तर पर सहायक अभियंता के रूप में अवशोषित या पदोन्नत होने या राजमार्ग विभाग में उनके द्वारा पहले से ही प्रदान की गई सेवा का लाभ दिए जाने का कोई दावा नहीं किया गया था। पूरे मामले पर विचार करने के बाद, हमें उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता है। उस स्तर पर सहायक अभियंता के रूप में अवशोषित या पदोन्नत होने या राजमार्ग विभाग में उनके द्वारा पहले से ही प्रदान की गई सेवा का लाभ दिए जाने का कोई दावा नहीं किया गया था। पूरे मामले पर विचार करने के बाद, हमें उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता है। उस स्तर पर सहायक अभियंता के रूप में अवशोषित या पदोन्नत होने या राजमार्ग विभाग में उनके द्वारा पहले से ही प्रदान की गई सेवा का लाभ दिए जाने का कोई दावा नहीं किया गया था। पूरे मामले पर विचार करने के बाद, हमें उच्च

न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असहमत होने का कोई कारण नहीं दिखता है।

32. तद्नुसार अपीलें खारिज की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस टुल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्वेता परमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अवीस्करणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा मे समझाने के लिये सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देय के लिये इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।